आज का मौसम

अधिकतम 38° C
न्यूनतम 30° C
सूर्य अस्त (आज) 7:20
सूर्य उदय (कल) 5:33

दैनिक समाचार पत्र

जीत समाचार

जीत सच्ची खबर की

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश

वर्ष : 13 | अंक : 299 | मूल्य : 2 रू | पृष्ठ : 8

शुक्रवार
17 जुलाई 2026

RNI NO : PUNHIN/2013/60106 | www.zeetsamachar.com

अनमोल वचन

"जिस तरह कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से गंदा नहीं होता उसी तरह आध्यात्मिक व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से विचलित या माया से अशुद्ध नहीं होता।"

संक्षिप्त न्यूज़

आतंकी वित्तपोषण और अवैध घुसपैठ मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 13 स्थानों पर छापेमारी

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आतंकी वित्तपोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में गुरुवार को देशभर में 13 स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में की गई।

ईडी के अनुसार, छापेमारी पश्चिम बंगाल के कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और मुर्शिदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद (बल्लभगढ़), उत्तर प्रदेश के सहारनपुर (देवबंद), दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर की गई।

यह मामला उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित है। आरोप है कि एक संगठित गिरोह रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, उनके लिए फर्जी भारतीय पहचान पत्र तैयार करवाने तथा देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में शामिल था।

तलाशी के दौरान पश्चिम बंगाल के कलिकपुर स्थित हरौरा अल-जमियातुल इस्लामिया दारुल उलूम परिसर से लगभग 40 लाख रुपये नकद और सोने के सिक्के बरामद किए गए।

जांच में एक ऐसे वित्तीय नेटवर्क का भी खुलासा होने का दावा किया गया है, जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाओं की भूमिका सामने आई है। ईडी के अनुसार, इन संस्थाओं पर बड़ी मात्रा में विदेशी चंदा प्राप्त कर उसे विभिन्न बैंक खातों और बिचौलियों के माध्यम से कथित अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल करने का संदेह है।

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि नकद निकासी और कई छोटी-छोटी धनराशि के लेन-देन के जरिए संदिग्ध लाभार्थियों तक पैसा पहुंचाया गया। ईडी ने कहा कि मामले की जांच जारी है और बरामद दस्तावेजों व डिजिटल साक्ष्यों की विस्तृत जांच की जा रही है।

सबरीमला मंदिर के कपाट खुले, पहले ही दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़

तिरुवनंतपुरम। केरल के प्रसिद्ध सबरीमला भगवान अयप्पा मंदिर के कपाट मलयालम माह कर्कटकम की मासिक पूजा के लिए गुरुवार शाम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। मंदिर खुलते ही पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे, जिससे सन्निधानम क्षेत्र में भारी भीड़ देखने को मिली।

मंदिर प्रशासन के अनुसार, कपाट खुलने के पहले दिन कोई विशेष पूजा या धार्मिक अनुष्ठान आयोजित नहीं किया गया। हालांकि, केरल के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक और अन्य पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे।

मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान और नियमित पूजा-अर्चना शुक्रवार सुबह पांच बजे से शुरू होगी, जो मलयालम माह कर्कटकम के दौरान 21 जुलाई तक जारी रहेगी। इस अवधि में प्रतिदिन विशेष पूजा, अभिषेक और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री मोदी कल दिखाएंगे देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी

संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली/जींद। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच संचालित होगी और भारत के रेलवे इतिहास में स्वच्छ, आधुनिक और हरित परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित इस हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा, जहां हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली रेलगाड़ियां संचालित होती हैं। इस सूची में जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देश पहले से शामिल हैं।

रेल मंत्रालय के अनुसार, इस ट्रेन को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि जींददृसोनीपत रेलखंड पर यह सुरक्षा मानकों और ट्रैक की क्षमता को ध्यान में रखते हुए अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से संचालित होगी।

हाइड्रोजन ट्रेन से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना भारतीय रेलवे के हरित ऊर्जा मिशन और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई मजबूती प्रदान करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में ऐसी ट्रेनों का विस्तार देश के अन्य रेल मार्गों पर भी किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस ऐतिहासिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाए जाने के साथ ही भारतीय रेलवे स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन के एक नए युग में प्रवेश करेगा।?

महाप्रभु जगन्नाथ की भक्ति और जनसेवा का संदेश, पीएम मोदी ने साझा किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का लेख

संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति अपनी आजीवन आस्था, आध्यात्मिक अनुभवों और जनसेवा की प्रेरणा पर लिखे गए भावपूर्ण लेख को सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति का यह लेख श्रद्धा, सेवा और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का प्रेरणादायक संदेश देता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने लेख के माध्यम से बचपन की स्मृतियों से लेकर जीवन को दिशा देने वाले आध्यात्मिक अनुभवों का बेहद आत्मीयता से वर्णन किया है। उन्होंने महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा और आस्था को शब्दों में व्यक्त किया है।

प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से राष्ट्रपति के उस भाव का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने भगवान जगन्नाथ की विश्वविख्यात रथ यात्रा की भव्यता और उसके आध्यात्मिक महत्व का वर्णन किया है। राष्ट्रपति ने लिखा है कि यही आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा उन्हें जीवनभर जनसेवा के मार्ग पर प्रेरित और मार्गदर्शित करती रही है।

पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति का यह लेख केवल व्यक्तिगत अनुभवों का संग्रह नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और भारतीय संस्कृति के मूल्यों का सशक्त संदेश भी है। उन्होंने लोगों से इस प्रेरणादायक लेख को पढ़ने का आग्रह करते हुए कहा कि यह आध्यात्मिक चेतना और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण की भावना को और मजबूत करता है।

महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति गहरी श्रद्धा, आध्यात्मिक मूल्यों और जनसेवा के आदर्शों को समर्पित यह लेख देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत माना जा रहा है।

जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक से मिले अरविंद केजरीवाल

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की उठाई मांग

संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचकर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए युवाओं और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार से संवाद करने की अपील की।

मीडिया से बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार को युवाओं की आवाज और सोनम वांगचुक द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों को गंभीरता से सुनना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि जनभावनाओं की अनदेखी करना किसी भी सरकार के लिए उचित नहीं होगा।

केजरीवाल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनकी जगह सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जाए।

यह मांग आम आदमी पार्टी की राजनीतिक प्रतिक्रिया है। इस पर केंद्र सरकार या शिक्षा मंत्रालय की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

टीबी मुक्त भारत अभियान में आई-ड्रोन बना वरदान,

जांच का समय 15 से घटकर 5 दिन, खर्च 9,451 से घटकर 91 रुपए

नई दिल्ली(एजेंसी)। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की 'आई-ड्रोन' पहल ने टीबी मुक्त भारत अभियान को नई गति दी है। हाल ही में किए गए एक अध्ययन में सामने आया है कि ड्रोन के माध्यम से टीबी मरीजों के बलगम के नमूनों को जांच प्रयोगशाला तक पहुंचाने से जांच प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज, आसान और किफायती हो गई है। इससे दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों का समय और आर्थिक बोझ दोनों में भारी कमी आई है।

यह अध्ययन तेलंगाना के यादद्री-भुवनगिरी जिले में एम्स बीबीनगर और राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के सहयोग से किया गया। अध्ययन में पारंपरिक व्यवस्था और ड्रोन आधारित नई प्रणाली की तुलना की गई।

जांच का समय 15 दिन से घटकर 5 दिन : अध्ययन में 840 लोगों को शामिल किया गया। परिणामों के अनुसार, ड्रोन से नमूने भेजने के बाद टीबी जांच पूरी होने का औसत समय 15 दिन से घटकर केवल 5 दिन रह गया। इससे मरीजों में बीमारी की पुष्टि जल्दी हो सकी और डह्क्टर समय पर उपचार शुरू करने में सक्षम हुए।

मरीजों का खर्च 9,451 से घटकर सिर्फ 91 रुपए : अध्ययन में यह भी पाया गया कि पहले मरीजों को जांच के लिए यात्रा, मजदूरी के नुकसान और अन्य खर्च मिलाकर औसतन 9,451 रुपए खर्च करने पड़ते थे। वहीं ड्रोन आधारित व्यवस्था लागू होने के बाद यह खर्च घटकर औसतन केवल 91 रुपए रह गया। कई मरीजों को तो अपने गांव के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ही नमूना जमा करने के कारण यात्रा पर कोई खर्च नहीं करना पड़ा।

गांव के पास ही मिली जांच की सुविधा : नई व्यवस्था को 'हब एंड स्पोक मॉडल' के तहत लागू किया गया, जिसमें 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 60 उप-स्वास्थ्य केंद्र और चार टीबी इकाइयों को आपस में जोड़ा गया। बलगम के नमूने स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों से ड्रोन के जरिए सीधे जांच प्रयोगशाला भेजे गए, जिससे लोगों को लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं रही।

स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक का बड़ा योगदान : आईसीएमआर के महानिदेशक एवं स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव डॉ. राजीव बहल ने कहा कि समय पर और सस्ती जांच की सुविधा भारत से टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से भौगोलिक चुनौतियों को दूर कर दूरस्थ क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सकती हैं।

भविष्य में और बढ़ेगा दायरा : स्वास्थ्यकर्मियों ने भी माना कि ड्रोन के उपयोग से जांच में देरी कम हुई और कार्यक्षमता बढ़ी। हालांकि मौसम, ड्रोन की भार क्षमता और कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण जैसी चुनौतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह मह्डल भविष्य में देश के अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम बन सकता है।

आईसीएमआर की आई-ड्रोन पहल के तहत भविष्य में टीके, दवाइयां, रक्त उत्पाद, जांच के नमूने और अन्य आवश्यक चिकित्सा सामग्री को सुरक्षित एवं तेजी से पहुंचाने की दिशा में भी लगातार कार्य किया जा रहा है।

भारत-बेल्जियम की पहली रणनीतिक वार्ता, व्यापार, रक्षा और निवेश सहयोग को मिलेगा नया विस्तार

संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। भारत और बेल्जियम ने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से 15 जुलाई 2026 को पहली भारत-बेल्जियम रणनीतिक वार्ता आयोजित की। दोनों देशों ने बदलते वैश्विक परिदृश्य में राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की।

यह रणनीतिक वार्ता भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी के तहत नियमित और परिणामोन्मुख राजनीतिक संवाद का नया मंच बनेगी। बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री मैक्सिम प्रेवो ने की।

बैठक में व्यापार एवं निवेश, हरित ऊर्जा, नवाचार और प्रौद्योगिकी, संपर्क, रक्षा एवं सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा लोगों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

बेल्जियम के विदेश मंत्री मैक्सिम प्रेवो ने कहा कि मार्च 2025 का बेल्जियम आर्थिक मिशन दोनों देशों के मजबूत आर्थिक संबंधों का प्रमाण है। उन्होंने विश्वास जताया कि व्यापार, निवेश और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भविष्य में और अधिक गति पकड़ेगा।

विदेश मंत्री डह्. एस. जयशंकर ने कहा कि यूरोप के साथ भारत के संबंधों में बेल्जियम का विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि यह रणनीतिक वार्ता दोनों देशों की साझा क्षमताओं का बेहतर उपयोग करते हुए ठोस और दीर्घकालिक परिणाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

दोनों देशों ने भविष्य में नियमित उच्चस्तरीय रणनीतिक बैठकों के आयोजन पर सहमति जताई। वर्ष के अंत में प्रस्तावित उच्चस्तरीय यात्राओं के दौरान कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय पहलों को आगे बढ़ाने की भी योजना बनाई गई है।

रणनीतिक वार्ता के साथ भारत-यूरोपीय संघ व्यापार मंच का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारत, बेल्जियम और अन्य यूरोपीय देशों के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हुए, जबकि बेल्जियम की ओर से फ्लैंडर्स और वालोनिया के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

बैठक में प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के संदर्भ में व्यापार और निवेश के नए अवसरों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। दोनों देशों ने भविष्य की चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए मजबूत, महत्वाकांक्षी और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

रक्षा से खेल तक, पीएम मोदी की यात्रा से भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मिली नई मजबूती : फिलिप ग्रीन

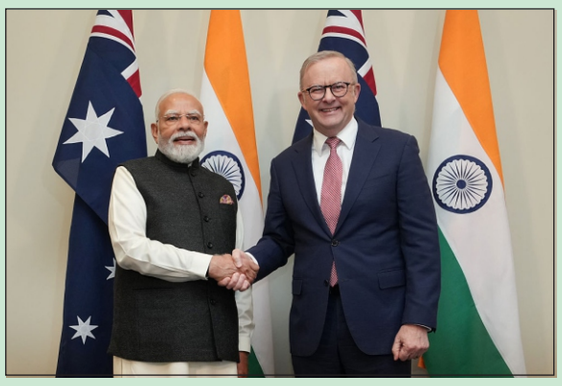

नई दिल्ली(एजेंसी)। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ओएएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अह्स्ट्रेलिया यात्रा को ऐतिहासिक और उपलब्धियों से भरपूर बताते हुए कहा कि इस दौरे ने भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नई दिशा दी है तथा दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाया है।

सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट की श्रृंखला में फिलिप ग्रीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की साझा दृष्टि और मजबूत नेतृत्व के कारण रक्षा, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, अंतरिक्ष, खेल और सांस्कृतिक सहयोग जैसे अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग को नई ऊंचाई : उच्चायुक्त ने बताया कि दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा के जरिए सैन्य साझेदारी को और मजबूत किया गया है। इसके तहत अधिक उन्नत संयुक्त सैन्य अभ्यास, क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर नियमित परामर्श और रक्षा सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा।

इंडो-पैसिफिक में बढ़ेगा समुद्री सहयोग : उन्होंने कहा कि 'समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप' और दोनों देशों के तटरक्षक बलों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षित समुद्री व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

ऊर्जा, तकनीक और महत्वपूर्ण खनिजों पर जोर : फिलिप ग्रीन ने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ऊर्जा सुरक्षा पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अह्स्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम निर्यात का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, आपूर्ति श्रृंखला और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है।

शिक्षा और कौशल विकास को मिलेगा बढ़ावा : उन्होंने कहा कि फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी को भारत में अपना परिसर स्थापित करने की मंजूरी मिल चुकी है, जबकि अन्य ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय भी भारत में अपनी मौजूदगी का विस्तार कर रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी नई साझेदारियों की शुरुआत हुई है।

गगनयान मिशन में ऑस्ट्रेलिया करेगा सहयोग : उच्चायुक्त ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के कोकोस द्वीपों के माध्यम से भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष ट्रैकिंग सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे दोनों देशों का अंतरिक्ष सहयोग और मजबूत होगा।

खेल और सांस्कृतिक संबंध भी होंगे मजबूत : फिलिप ग्रीन ने कहा कि अह्स्ट्रेलिया तमिलनाडु से जुड़ी पवित्र भारतीय कलाकृतियों की वापसी में सहयोग करेगा। वहीं नए स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप के तहत खेल विज्ञान, प्रशिक्षण, तकनीक और बड़े खेल आयोजनों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहली बार बिग बैश लीग का उद्घाटन मुकाबला भारत में आयोजित किया जाएगा, जिसके साथ एक सप्ताह तक 'गुड डे नमस्ते' उत्सव भी मनाया जाएगा।

साझेदारी को मिलेगी नई गति : फिलिप ग्रीन ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत और अह्स्ट्रेलिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच शुरू की गई नई पहलें भविष्य में व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जन-जन के संबंधों को और अधिक मजबूत बनाएंगी।

महंगाई पर लगाम के लिए दक्षिण कोरिया के सेंट्रल बैंक ने तीन साल बाद बढ़ाई ब्याज दर

सियोल(एजेंसी)। दक्षिण कोरिया के केंद्रीय बैंक बैंक ऑफ कोरिया (बीओके) ने तीन वर्ष से अधिक समय बाद पहली बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में वृद्धि की है। यह फैसला पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण महंगाई के बढ़ते दबाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद बैंक ऑफ कोरिया ने अपनी बेंचमार्क नीति दर में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 2.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.75 प्रतिशत कर दिया।

बैंक ऑफ कोरिया के गवर्नर शिन ह्यून सोंग ने बताया कि मौद्रिक नीति समिति के सभी सात सदस्यों ने सर्वसम्मति से ब्याज दर बढ़ाने के निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और उससे बढ़ी महंगाई की आशंकाओं को देखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना केंद्रीय बैंक की प्राथमिकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ब्याज दर में यह बढ़ोतरी महंगाई पर नियंत्रण रखने के साथ-साथ दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इससे ऋण लेने की लागत बढ़ सकती है और उपभोक्ता तथा कारोबारी गतिविधियों पर भी इसका असर पड़ने की संभावना है।

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद में तैयारियों का लिया जायजा

जीत समाचार ब्यूरों

हरियाणा/जींद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रवार को प्रस्तावित हरियाणा दौरे से एक दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद पहुंचकर कार्यक्रम स्थल और विभिन्न व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर और सुचारु रूप से पूरी करने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर को लेकर मुख्यमंत्री ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के जींद दौरे के सभी कार्यक्रम पूरी तरह पर्यावरण-अनुकूल (इको-फ्रेंडली) होंगे। उन्होंने अधिकारियों से हर व्यवस्था को उच्च स्तर पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने एकलव्य स्टेडियम के सामने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) मैदान में आयोजित होने वाली 'विकसित भारतदृविकसित हरियाणा' रैली की तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने मंच, सुरक्षा, यातायात, पेयजल, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा हरियाणा और भारतीय रेलवे के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस दौरान देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के साथ-साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

नीलोखेड़ी के इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाना

हम सबकी जिम्मेदारी - डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान

जीत समाचार हरियाणा/नीलोखेड़ी। गुरु ब्रह्मानंद राजकीय पहलिटेक्निक, नीलोखेड़ी में आयोजित वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन, कड़ी मेहनत और बड़े सपने देखने की प्रेरणा देते हुए कहा कि नीलोखेड़ी का समृद्ध इतिहास और विरासत नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

अपने संबोधन में डॉ. चौहान ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र निर्माण का आधार है। उन्होंने विद्यार्थियों से जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करने और अनुशासन को सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बनाने का आह्वान किया।

उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि यही युवा भविष्य में देश और समाज का नाम रोशन करेंगे।

समारोह के दौरान विभिन्न शैक्षणिक, तकनीकी, सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में संस्थान के प्राचार्य, शिक्षकगण, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। सभी ने सम्मानित विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

करनाल में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, तीन कॉलोनियां और एक अवैध निर्माण ध्वस्त

जीत समाचार करनाल। जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग ने पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अवैध कॉलोनियों तथा एक अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

जिला नगर योजनाकार ने बताया कि यह कार्रवाई नियमानुसार की गई है। अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना वैध स्वीकृति के विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। लोगों के हितों की सुरक्षा और सुनियोजित शहरी विकास सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्लॉट या संपत्ति की खरीद से पहले संबंधित विभाग से उसकी वैधता की पूरी जांच कर लें। साथ ही केवल अधिकृत और स्वीकृत कॉलोनियों में ही निवेश करें तथा प्रॉपर्टी डीलरों के झांसे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से बचें।

सीजेएम ने जांच अधिकारियों को दी 'जीरो एफआईआर' और कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी

जीत समाचार हरियाणा/नारनौल(ब्यूरों)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की चेयरपर्सन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. रितु वाई.के. बहल के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर सेंटर के कॉन्फ्रेंस हॉल में पुलिस एवं जांच अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) नीलम कुमारी ने की।

कार्यशाला में सीजेएम नीलम कुमारी ने पुलिस अधिकारियों को प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने की प्रक्रिया, आरोपी की गिरफ्तारी तथा जांच के दौरान अपनाई जाने वाली कानूनी प्रक्रियाओं और नियमों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने 'जीरो एफआईआर' की अवधारणा समझाते हुए कहा कि किसी भी पीड़ित को क्षेत्राधिकार के आधार पर राहत से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और पुलिस का पहला दायित्व उसे तत्काल कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है।

उन्होंने जांच अधिकारियों को जांच से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं पर प्रस्तुतीकरण (पीपीटी) के माध्यम से प्रशिक्षण दिया और कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य पुलिस एवं न्यायपालिका के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा किशोर न्याय और अन्य संवेदनशील कानूनी विषयों के प्रति अधिकारियों को जागरूक बनाना है।

सीजेएम ने पीड़ित मुआवजा योजना के बारे में भी जानकारी देते हुए कहा कि एसिड अटैक, दुष्कर्म, हत्या तथा गंभीर दुर्घटनाओं जैसे मामलों के पीड़ितों और उनके आश्रितों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने अधिकारियों से आमजन को इस योजना के प्रति अधिक जागरूक करने का आह्वान किया।

उन्होंने 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों से अधिक से अधिक लंबित एवं शमनीय मामलों का आपसी सहमति से निपटारा कराने के लिए लोगों को प्रेरित करने की अपील की, ताकि न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम किया जा सके।

सीजेएम नीलम कुमारी ने बताया कि किसी भी प्रकार की निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए नागरिक राष्ट्रीय हेल्पलाइन 15100 तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नारनौल के हेल्पलाइन नंबर 01282—250322 पर संपर्क कर सकते हैं।

कार्यशाला में डीएसपी भारत भूषण, जिले के सभी थाना प्रबंधक, जांच अधिकारी, जुवेनाइल वेलफेयर अधिकारी तथा अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर -
'शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।'

पंजाब में कानून-व्यवस्था और गैंगस्टर नेटवर्क -राज्य के सामने बड़ी चुनौती

पंजाब लंबे समय से कानून-व्यवस्था और संगठित अपराध की चुनौतियों का सामना कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में गैंगस्टर नेटवर्क, नशा तस्करी, अवैध हथियारों की सप्लाई, फिरौती, लक्षित हत्याओं और सीमा पार से होने वाली आपराधिक गतिविधियों ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के सामने गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। हालांकि पंजाब पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) लगातार इन नेटवर्कों पर कार्रवाई कर रहे हैं, फिर भी बदलते तौर-तरीकों के कारण यह समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई है।

पंजाब की अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसका फायदा उठाकर कई बार ड्रोन के माध्यम से नशीले पदार्थ, हथियार और गोला-बारूद भेजने के प्रयास किए जाते हैं। सुरक्षा एजेंसियां नियमित रूप से ऐसे ड्रोन को पकड़ने और तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के अभियान चलाती हैं। इन गतिविधियों का सीधा संबंध कई बार संगठित अपराध और गैंगस्टर गिरोहों से भी जोड़ा जाता है।

गैंगस्टर नेटवर्क अब केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार कई मामलों में विदेशों में बैठे अपराधी सोशल मीडिया, इंटरनेट कॉलिंग और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के जरिए अपने नेटवर्क का संचालन करते हैं। वे रंगदारी वसूलने, धमकी देने और आपराधिक घटनाओं की साजिश रचने के लिए तकनीक का उपयोग करते हैं। इससे पुलिस के सामने जांच और अपराध नियंत्रण की चुनौती और बढ़ जाती है।

राज्य में समय-समय पर गैंगवार, फिरौती, कारोबारियों को धमकियां, अवैध हथियारों की बरामदगी और अपराधियों की गिरफ्तारियों की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इन घटनाओं से आम जनता में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती है और व्यापारिक माहौल पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना सरकार और पुलिस की प्राथमिकताओं में शामिल है।

पंजाब पुलिस ने हाल के वर्षों में कई बड़े अभियान चलाकर गैंगस्टर नेटवर्क पर शिकंजा कसने का दावा किया है। विशेष ऑपरेशन सेल, एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स , साइबर विशेषज्ञों और खुफिया एजेंसियों के सहयोग से अनेक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अवैध हथियारों की बरामदगी, बैंक खातों की जांच, संपत्तियों पर कार्रवाई और वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं।

नशा तस्करी और गैंगस्टर नेटवर्क के बीच संबंध भी चिंता का विषय है। जांच एजेंसियों का मानना है कि कई आपराधिक गिरोह नशे के कारोबार से आर्थिक लाभ प्राप्त कर अपने नेटवर्क को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। इसलिए नशे के खिलाफ अभियान और गैंगस्टर नेटवर्क पर कार्रवाई को एक-दूसरे से जुड़ा हुआ माना जाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल पुलिस कार्रवाई से इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। इसके लिए युवाओं को रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेल सुविधाएं, कौशल विकास और नशामुक्ति कार्यक्रमों से जोड़ना भी उतना ही आवश्यक है। समाज, परिवार, शैक्षणिक संस्थानों और प्रशासन को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना होगा, जिससे युवा अपराध और नशे से दूर रहें।

इसके अलावा आधुनिक तकनीक का उपयोग, बेहतर खुफिया तंत्र, सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, राज्यों के बीच समन्वय और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाकर संगठित अपराध पर अधिक प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।

निष्कर्ष : कानून-व्यवस्था और गैंगस्टर नेटवर्क पंजाब के सामने एक गंभीर चुनौती हैं, लेकिन लगातार पुलिस कार्रवाई, सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय और समाज के सहयोग से इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में प्रयास जारी हैं। दीर्घकालिक सफलता के लिए अपराध नियंत्रण के साथ-साथ युवाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर भी समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है।

कमल पवार (सम्पादक)

आज की प्रमुख हस्ती

बच्चों में मोबाइल का बढ़ता दुरुपयोग: ज्ञान से अधिक मनोरंजन की ओर बढ़ते कदम

अजय कुमार
(एम.ए. राजनीति शास्त्र एवं बी. एड)
जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश

आज का युग डिजिटल तकनीक का युग है। मोबाइल फोन ने शिक्षा, संचार और जानकारी प्राप्त करने के अनेक नए अवसर प्रदान किए हैं। यदि इसका सही उपयोग किया जाए, तो यह बच्चों के लिए ज्ञान का एक प्रभावी माध्यम बन सकता है। कोरोना महामारी के दौरान अहनलाइन कक्षाओं और घर से पढ़ाई की आवश्यकता के कारण बच्चों के हाथों में मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरण बड़ी संख्या में पहुँचे। उस समय यह शिक्षा का आवश्यक साधन था, लेकिन महामारी समाप्त होने के बाद भी अनेक बच्चों में मोबाइल के अत्यधिक उपयोग की आदत बनी रही।

आज अधिकांश बच्चे मोबाइल का उपयोग पढ़ाई और सीखने की अपेक्षा मनोरंजन, ऑनलाइन गेम, शॉर्ट वीडियो और सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने के लिए कर रहे हैं। यह स्थिति अभिभावकों, शिक्षकों और समाज के लिए चिंता का विषय बन चुकी है।मोबाइल का अत्यधिक उपयोग बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आँखों की समस्या, नींद में कमी, एकाग्रता में गिरावट और शारीरिक गतिविधियों में कमी जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं। कई बच्चे परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने के बजाय आभासी दुनिया में अधिक व्यस्त रहने लगे हैं। इससे उनके व्यवहार, अध्ययन और व्यक्तित्व पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

विडंबना यह है कि जिस मोबाइल में विश्वभर का ज्ञान उपलब्ध है, उसका उपयोग बहुत कम बच्चे सीखने के लिए करते हैं। यदि प्रतिदिन कुछ समय शैक्षिक वीडियो, ई-पुस्तकों, विज्ञान, भाषा, सामान्य ज्ञान और नई तकनीकों को सीखने में लगाया जाए, तो मोबाइल एक उत्कृष्ट शिक्षक बन सकता है। दुर्भाग्य से अधिकांश समय मनोरंजन में ही व्यतीत हो जाता है।

इस समस्या का समाधान केवल बच्चों से अपेक्षा करने से नहीं होगा। अभिभावकों और शिक्षकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम की उचित सीमा तय करनी चाहिए, पढ़ाई, खेल-कूद और पारिवारिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाना चाहिए तथा उन्हें मोबाइल का सकारात्मक और रचनात्मक उपयोग सिखाना चाहिए। साथ ही, बड़े भी स्वयं जिम्मेदारी से मोबाइल का उपयोग कर बच्चों के सामने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें।

मोबाइल न तो पूरी तरह अच्छा है और न ही बुरा। उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस उद्देश्य से करते हैं। यदि बच्चे मोबाइल को ज्ञान, रचनात्मकता और कौशल विकास का साधन बनाएँ, तो वही तकनीक उनके उज्ज्वल भविष्य का आधार बन सकती है। लेकिन यदि इसका अनियंत्रित और अत्यधिक उपयोग जारी रहा, तो यह उनके बचपन, शिक्षा और भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है।

आज आवश्यकता मोबाइल छोड़ने की नहीं, बल्कि मोबाइल का सही, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण उपयोग सीखने और सिखाने की है। यही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की सबसे बड़ी कुंजी है।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर (भारत)

1. आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (पुलिस, फायर, और एंबुलेंस)

112	आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (पुलिस, फायर, और एंबुलेंस)
100	पुलिस (Police)
101	फायर ब्रिगेड (Fire Brigade)
102 / 108	एम्बुलेंस सेवा (Ambulance)
1091	महिला हेल्पलाइन (Women Helpline)
1098	चाइल्ड हेल्पलाइन (Child Helpline)
104	स्वास्थ्य हेल्पलाइन (Health Helpline/Medical Advice)
1915	पर्यटन हेल्पलाइन (Tourist Helpline)
1930	साइबर अपराध (Cyber Crime)
139	रेलवे पूछताछ / सुरक्षा (Railway Enquiry / Security)
1363	पर्यटन हेल्पलाइन (Tourist Helpline)
1033	सड़क दुर्घटना या राष्ट्रीय राजमार्ग आपातकाल (Road Accident / National Highway Emergency)
14567	बुजुर्ग हेल्पलाइन (Elder Line)
1551	किसान कॉल सेंटर (Kisan Call Center)
1906	गैस सिलेंडर (LPG) रिसाव या आपातकाल (LPG Gas Leak / Emergency)

2. राज्य / बिजली बोर्ड हेल्पलाइन नंबर (टोल-फ्री)

राज्य	हेल्पलाइन नंबर (टोल-फ्री)	वैकल्पिक संपर्क नंबर / वेबसाइट
हिमाचल प्रदेश (HPSEBL)	1912	1800-180-8060 | www.hpseb.in
उत्तर प्रदेश (UPPCL / अन्य)	1912	1800-180-8752 | www.uppcl.org
दिल्ली (BSES/TPDDL)	1912	वेबसाइट के माध्यम से चैटबॉट सपोर्ट www.bsesdelhi.com / www.tatapower-ddl.com
पंजाब (PSPCL)	1912	1800-180-1512 | www.pspcl.in
हरियाणा (DHBVN/UHBVN)	1912	1800-180-1833 | www.dhbvn.org.in / www.uhbvn.com
मध्य प्रदेश (MPPKVVCL)	1912	1800-233-1266, WhatsApp: 9425807257 www.mpez.co.in
उत्तराखंड (UPCL)	1912	1800-419-0405 | www.upcl.org

3. राज्यवार जल हेल्पलाइन नंबर

राज्य / विभाग	हेल्पलाइन नंबर	विवरण / वेबसाइट
केंद्रीय / राष्ट्रीय	1800-121-2164	जल जीवन मिशन का टोल-फ्री नंबर | www.jaljeevanmission.gov.in
हिमाचल प्रदेश (स्थानीय)	1800-180-8009, 1100	जल शक्ति विभाग (SNK), शिकायत निवारण केंद्र
दिल्ली	1916	दिल्ली जल बोर्ड (24x7) | www.delhijalboard.nic.in
उत्तर प्रदेश	1076	सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) | www.up.gov.in
बिहार	1800-123-1121	पीएचईडी (PHED) पेयजल शिकायत | www.prdbihar.gov.in
राजस्थान	1800-180-6088	जलदाय विभाग (PHED) | www.jalday.rajasthan.gov.in
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (सभी राज्य)	181 या 1902	सभी राज्यों की शिकायत और जानकारी के लिए

4. राज्यवार परिवहन (बस) हेल्पलाइन नंबर

राज्य / निगम	हेल्पलाइन नंबर	विवरण / उपयोग
हिमाचल प्रदेश (HRTC)	1100, 1800 180 8185	24/7 हेल्पलाइन, पूछताछ और शिकायत निवारण
दिल्ली (DTC)	011-22968836	आईएसबीटी (ISBT) पूछताछ
उत्तर प्रदेश (UPSRTC)	149, 1800 1800 151	24/7 टोल-फ्री सुविधा
राजस्थान (RSRTC)	181	मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता
चंडीगढ़ (CTU)	1800 274 7400	टोल फ्री नंबर

इन हेल्पलाइन नंबरों को सेव करें और जरूरत पड़ने पर उपयोग करें। यह आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

दैनिक समाचार पत्र
जीत समाचार
जीत सच्ची ख़बर की

मुद्रक, प्रकाशक व सम्पादक : कमल पवार द्वारा 11368, पवित्र नगर, वालिया कालोनी हैबोवाल कलां, लुधियाना से प्रकाशित एंव जीत लुधियाना प्रिंटर्स हैबोवाल लुधियाना से मुद्रित।

सम्पादक : कमल पवार इस अंक मे प्रकाशित एंव समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादक हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा उत्पन्न समस्त विवाद लुधियाना न्यायालय के अधीन होगे।

R.N.I NO. PUN/HIN/2013/60106

Contact us :- +91-98030-25111.

प्रधानमंत्री के दौरे से पहले डीजीपी पंजाब ने जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

जीत समाचार जालंधर। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर सुरक्षा तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में पंजाब पुलिस के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान डीजीपी ने स्टेशन परिसर में सुरक्षा प्रबंधों, अधिकारियों एवं सुरक्षा बलों की तैनाती तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने के निर्देश दिए।

डीजीपी ने यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान किसी भी प्रकार की चूक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए।

इस अवसर पर पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद रहे।

ट्यिाला में विजिलेंस ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, वाटर रिसोर्स विभाग का क्लर्क 10,500 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार

जीत समाचार पटियाला(ब्यूरों)। भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाटर रिसोर्स विभाग के देवीगढ़ मंडल, पटियाला में तैनात असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क सुखपाल सिंह को 10,500 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में विजिलेंस ब्यूरो थाना, पटियाला रेंज में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

शिकायत के आधार पर हुई कार्रवाई : प्रवक्ता के अनुसार, यह कार्रवाई गांव गज्जूमाजरा, तहसील एवं जिला पटियाला निवासी हरजिंदर सिंह की शिकायत पर की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके और उसके भाई के खेतों में नहर के पानी के लिए मोगा लगाने के बदले आरोपी ने पहले 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। बाद में सौदा 14,000 रुपये में तय हुआ, जिसमें से 3,500 रुपये पहले ही ले लिए गए थे और शेष 10,500 रुपये की मांग की जा रही थी।

जाल बिछाकर रंगे हाथों किया गिरफ्तार : शिकायत का सत्यापन करने के बाद विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और आरोपी सुखपाल सिंह को 10,500 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की पूरी राशि भी बरामद कर ली गई।

जांच जारी, लोगों से सहयोग की अपील : विजिलेंस ब्यूरो ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है। यदि जांच में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ब्यूरो ने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी कार्य के बदले रिश्वत मांगता है तो इसकी सूचना तुरंत विजिलेंस ब्यूरो को दें, ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

पद्मश्री सम्मान के बाद संत निरंजन दास जी का संगत ने किया भव्य स्वागत, जगजीत सिंह जानकी ने दी बधाई

जीत समाचार अमृतसर। डेरा सचखंड बल्लां के प्रमुख संत निरंजन दास जी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर देश-विदेश की संगत में खुशी की लहर है। डेरा सचखंड बल्लां में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और संत निरंजन दास जी को सिरोपा भेंट कर तथा पुष्प अर्पित कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर अमृतसर से श्री गुरु रविदास समुदाय के प्रमुख नेता जगजीत सिंह जानकी ने भी संत निरंजन दास जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने पद्मश्री सम्मान के लिए संत जी को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान केवल संत निरंजन दास जी का ही नहीं, बल्कि पूरे रविदासिया समाज, पंजाब और देश के लिए गर्व का विषय है।

जगजीत सिंह जानकी ने कहा कि संत निरंजन दास जी ने दशकों से श्री गुरु रविदास महाराज जी के समानता, भाईचारे और मानवता के संदेश को देश-विदेश में फैलाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक, सामाजिक और मानव सेवा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा दिया गया पद्मश्री सम्मान पूरी तरह से योग्य और प्रेरणादायक है।

इस दौरान संत निरंजन दास जी ने जगजीत सिंह जानकी को आशीर्वाद देते हुए समाज सेवा के कार्यों में निरंतर अग्रणी रहने और जनकल्याण के लिए कार्य करते रहने की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उन्हें सिरोपा भेंट कर सम्मानित भी किया गया।

जगजीत सिंह जानकी ने संत निरंजन दास जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका आशीर्वाद उन्हें समाज और मानवता की सेवा के लिए निरंतर प्रेरित करता रहेगा।

मेयर पदमजीत सिंह मेहता ने करनैल सिंह नगर में प्रीमिक्स सड़क निर्माण कार्य का किया शुभारंभ

जीत समाचार बठिंडा(ब्यूरों)। शहर में विकास कार्यों को गति देते हुए बठिंडा नगर निगम के मेयर पदमजीत सिंह मेहता ने वार्ड नंबर 27 स्थित करनैल सिंह नगर में प्रीमिक्स सड़क निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया।

इस अवसर पर नगर निगम के जेई अमित कुमार, चरणजीत सिंह भोला, बलराज सिंह, सुखदेव सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

मेयर पदमजीत सिंह मेहता ने कहा कि नगर निगम शहर के प्रत्येक वार्ड में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती हैं तथा करनैल सिंह नगर में प्रीमिक्स सड़क बनने से स्थानीय लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरा किया जाए, ताकि लोगों को लंबे समय तक इसका लाभ मिल सके।

मेयर ने कहा कि बठिंडा शहर के समग्र विकास के लिए नगर निगम योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहा है। शहर में सड़क, सीवरेज, पेयजल, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए कई विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि शहर का कोई भी वार्ड विकास कार्यों से वंचित नहीं रहेगा और नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे।

विजिलेंस ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, सहकारी समिति के इंस्पेक्टर को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

जीत समाचार पटियाला। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कोऑपरेटिव सोसाइटी तपा, जिला बरनाला में तैनात इंस्पेक्टर हर्ष बंसल को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी कोअहपरेटिव सोसाइटी तपा के सेवानिवृत्त सचिव जंग सिंह की शिकायत के आधार पर की गई।

प्रवक्ता के अनुसार, शिकायतकर्ता के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही थी। आरोप है कि इंस्पेक्टर हर्ष बंसल ने शिकायतकर्ता के सेवानिवृत्ति बकाया जारी करवाने और विभागीय जांच में उसके पक्ष में निर्णय दिलाने के बदले एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। बाद में यह सौदा 50 हजार रुपये में तय हुआ।

रिश्वत देने के बजाय शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो, पटियाला रेंज से संपर्क कर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत का सत्यापन करने के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में आरोपी को शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मौके से रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई।

इस संबंध में आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो थाना, पटियाला में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। विजिलेंस ब्यूरो ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट 21 से 23 अगस्त तक लगाएगा विशेष लोक अदालत, लंबित मामलों के आपसी समझौते से होंगे निपटारे

जीत समाचार गुरदासपुर। भारत का सुप्रीम कोर्ट 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य लंबे समय से लंबित मामलों का आपसी सहमति और वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यम से शीघ्र निपटारा करना है।

यह जानकारी देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरदासपुर के चेयरमैन दिलबाग सिंह जोहल ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या कम करना तथा पक्षकारों को सरल, त्वरित और कम खर्चीला न्याय उपलब्ध कराना है।

उन्होंने बताया कि विशेष लोक अदालत में ऐसे मामलों का निपटारा किया जाएगा, जिनका समाधान आपसी सहमति से संभव है। इनमें वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा मामले, सेवा विवाद, भूमि अधिग्रहण, उपभोक्ता विवाद तथा अन्य ऐसे दीवानी मामले शामिल हैं, जिन्हें कानून के तहत लोक अदालत में सुलझाया जा सकता है।

दिलबाग सिंह जोहल ने बताया कि गुरदासपुर जिले से संबंधित जिन मामलों की सूची सुप्रीम कोर्ट से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्राप्त हुई है, उनमें दोनों पक्षों को समन जारी किए जा चुके हैं। इन मामलों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरदासपुर द्वारा प्री-लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यदि प्री-लोक अदालत में दोनों पक्ष समझौते पर सहमत हो जाते हैं, तो उसकी रिपोर्ट मुख्यालय एसएएस नगर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट भेजी जाएगी, जहां 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित विशेष लोक अदालत में अंतिम समझौते को मंजूरी दी जाएगी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित तथा गुरदासपुर जिले से संबंधित मामलों के पक्षकारों से अपील की कि वे प्री-लोक अदालतों में भाग लेकर इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों में आपसी सहमति से विवादों का समाधान होने से समय और धन की बचत होती है तथा पक्षकारों के बीच सौहार्द और विश्वास भी मजबूत होता है।

100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन करने वाले पहले 100 बीएलओ होंगे सम्मानित, मानसा में प्रक्रिया 88 प्रतिशत पूरी

जीत समाचार ब्यूरों मानसा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त नवजोत कौर ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 की प्रगति की समीक्षा बैठक की। बैठक में मतदाता गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) एकत्र करने और उनके डिजिटाइजेशन कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बूथ लेवल अधिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए घोषणा की कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत 100 प्रतिशत एन्यूमरेशन फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा करने वाले पहले 100 बीएलओ को जिला प्रशासन द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा।

नवजोत कौर ने बताया कि मानसा जिले में अब तक 88 प्रतिशत डिजिटाइजेशन कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने शेष कार्य को जल्द पूरा करने के लिए सभी बीएलओ को सक्रियता और गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि मतदाताओं की सुविधा तथा प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से रविवार, 19 जुलाई को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में सभी बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाने, जमा करने तथा उनके डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे।

बैठक में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी बलजीत कौर (मानसा), गुरमीत कुमार (बुढलाडा), हरजिंदर सिंह जस्सल (सरदूलगढ़) तथा निर्वाचन तहसीलदार भूषण कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

हिमाचल में चार नए ई-डिपो होंगे स्थापित, 297 नई इलेक्ट्रिक बसें जल्द होंगी शामिल

जीत समाचार ब्यूरों शिमला। हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए एचआरटीसी निदेशक मंडल की 163वीं बैठक में चार नए ई-डिपो स्थापित करने और 297 नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि नादौन, हरोली, नाहन और ठियोग को ई-डिपो के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें नादौन, हरोली और ठियोग एचआरटीसी के नए डिपो होंगे, जबकि नाहन पहले से संचालित डिपो को ई-डिपो के रूप में विकसित किया जाएगा।

इन चारों डिपो से केवल इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। : उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 297 नई इलेक्ट्रिक बसों के परीक्षण और संचालन से संबंधित सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाएंगी, ताकि इन्हें जल्द प्रदेशवासियों की सेवा के लिए सड़क पर उतारा जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

टायर और पुर्जों की कमी पर जताई नाराजगी : बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री ने एचआरटीसी बसों में टायरों और अन्य आवश्यक पुर्जों की कमी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी बस का संचालन आवश्यक सामग्री के अभाव में प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने समय पर खरीद और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

खराब ई-बसों की जल्द होगी मरम्मत : एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने बताया कि शिमला में खराब पड़ी इलेक्ट्रिक बसों की मरम्मत जल्द शुरू की जाएगी। इसके लिए पीएमई बस कंपनी के साथ करार करने का निर्णय लिया गया है। कंपनी आवश्यक स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराने के साथ अपने इंजीनियरों के माध्यम से बसों की मरम्मत भी करेगी।

उन्होंने कहा कि नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और खराब बसों के शीघ्र मरम्मत कार्य से प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और पर्यावरण-अनुकूल यात्रा का लाभ मिलेगा।

जिला परिषद चंबा की नवनियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री सुक्खू से की शिष्टाचार भेंट

जीत समाचार शिमला। जिला परिषद चंबा की नवनियुक्त अध्यक्ष रेखा देवी और उपाध्यक्ष लियाकत अली खान ने शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दोनों जनप्रतिनिधियों को नई जिम्मेदारी संभालने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मुलाकात के दौरान चंबा जिले के विकास कार्यों, पंचायत स्तर पर जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा स्थानीय समस्याओं और विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार चंबा जिले के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जिला परिषद के जनप्रतिनिधि स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि चंबा जिले के विकास और जनहित से जुड़े प्रत्येक सार्थक सुझाव पर राज्य सरकार सकारात्मक और संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ कार्य करती रहेगी।

महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

जीत समाचार शिमला। पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 15 एवं 16 जुलाई 2026 को राज्य पंचायत संसाधन केंद्र , क्रेगनैनो, मशोबरा में आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

कार्यक्रम में प्रदेश के सभी 12 जिलों से 102 महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा पंचायती राज विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व कौशल को सुदृढ़ करना और स्थानीय शासन से जुड़े विषयों पर उनकी कार्यक्षमता को और प्रभावी बनाना था। प्रशिक्षण प्राप्त प्रतिनिधि भविष्य में अपने-अपने क्षेत्रों में मास्टर ट्रेनर के रूप में क्षमता निर्माण गतिविधियों का संचालन भी करेंगी।

दो दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक प्रावधान, ग्राम पंचायत विकास योजना, ग्राम सभा सुदृढ़ीकरण, वित्तीय प्रबंधन, डिजिटल गवर्नेंस, नेतृत्व एवं संचार कौशल, महिला सशक्तिकरण तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी अभिसरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण में समूह चर्चा, व्यावहारिक अभ्यास और अनुभव साझा करने जैसे सत्र भी आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से स्थानीय शासन से जुड़े व्यवहारिक पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

पंचायती राज विभाग ने कहा कि महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों का सशक्त नेतृत्व पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभाग ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों के सतत क्षमता निर्माण तथा महिला नेतृत्व को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

बैजनाथ पुलिस ने उद्घोषित अपराधी को किया गिरफ्तार

जीत समाचार बैजनाथ(अभिषेक न्यूज एडिटर)।कांगड़ा पुलिस ने फरार एवं उद्घोषित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तिलक राज (54 वर्ष) निवासी गांव मन्देहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी को माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, बैजनाथ द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत चल रहे एक मामले में 20 मार्च 2025 को उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

कांगड़ा पुलिस ने कहा कि फरार एवं उद्घोषित अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई का अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून से बचने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मंडी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 519 पेटी बीयर की अवैध खेप जब्त

जीत समाचार ब्यूरों मंडी। मंडी पुलिस ने आबकारी कानून के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना वैध लाइसेंस एवं परमिट के ले जाई जा रही 519 पेटी बीयर की अवैध खेप बरामद की है। इस संबंध में पुलिस थाना सदर, मंडी में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस के अनुसार, जब्त की गई खेप में 161 पेटी किंगफिशर बीयर और 358 पेटी टुबॉर्ग बीयर शामिल हैं। कुल 6,228 बीयर की बोतलें, जिनकी मात्रा लगभग 4,048.2 लीटर है, बरामद की गई हैं।

प्रारंभिक जांच में पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अवैध शराब की यह खेप कहां से लाई जा रही थी और इसे किस स्थान पर पहुंचाया जाना था। मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।

मंडी पुलिस ने कहा है कि प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार और आबकारी कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा तथा दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दिव्यांग सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए 31 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन

जीत समाचार ब्यूरों हमीरपुर।दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उनके लिए बेहतर एवं समावेशी वातावरण तैयार करने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों और प्रतिष्ठानों को इस वर्ष भी 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा।

उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि इन राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए पात्र व्यक्ति, संस्थाएं और संगठन 31 जुलाई तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर अहनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुरस्कारों से संबंधित विस्तृत जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट पर भी आवेदन प्रक्रिया और दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं।

उपायुक्त ने बताया कि इन पुरस्कारों का उद्देश्य दिव्यांगजनों के अधिकारों, समान अवसरों और समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करना है।

उन्होंने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे सभी पात्र व्यक्तियों, संस्थानों और संगठनों से अपील की कि वे 31 जुलाई से पहले अहनलाइन आवेदन कर इस राष्ट्रीय सम्मान के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करें।

पीजीआई चंडीगढ़ में आर्थोपेडिक्स सर्जरी के लिए डॉ. वरुण वालिया का चयन, क्षेत्र में खुशी की लहर

जीत समाचार ब्यूरों धर्मशाला। ज्वाहर नगर (धर्मशाला) निवासी डॉ. वरुण वालिया का देश के प्रतिष्ठित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ में आर्थोपेडिक्स सर्जरी में उच्च शिक्षा के लिए चयन हुआ है। उन्होंने यह सफलता इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से हासिल की है।

अब डॉ. वरुण वालिया पीजीआई चंडीगढ़ से आर्थोपेडिक्स सर्जरी में विशेषज्ञता प्राप्त करेंगे। उनकी इस उपलब्धि से धर्मशाला सहित पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

डॉ. वरुण वालिया इससे पहले बैजनाथ उपमंडल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महाकाल, पीएचसी सकरी तथा सिविल अस्पताल चढ़ियार में लगभग तीन वर्षों तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अपनी कार्यकुशलता, सरल स्वभाव और मरीजों के प्रति समर्पित सेवा के कारण उन्होंने क्षेत्र में एक विशेष पहचान बनाई।

डॉ. वरुण वालिया के पिता राजेश कुमार वालिया खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सेल्स अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हैं, जबकि उनकी माता अनुराधा वालिया गृहिणी हैं।

उनकी इस उल्लेखनीय सफलता पर परिजनों, मित्रों, शुभचिंतकों और क्षेत्रवासियों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं।

डॉ. वरुण वालिया ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, परिवारजनों, गुरुजनों और शुभचिंतकों के निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन एवं प्रेरणा को दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी अपनी विशेषज्ञता और अनुभव के माध्यम से मरीजों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का हरसंभव प्रयास करेंगे।